

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—126/2018/223 (2018/00126)

1. बजरंगलाल तेली पुत्र नन्दलाल, जाति तेली, नि० हॉस्पिटल रोड़, केकड़ी जिला अजमेर ।

अपीलांत

बनाम

1. रमेश पुत्र नन्दलाल, जाति तेली, नि० केकड़ी हाल नि० मकान नंबर 2679 चटाई मौहल्ला, नसीराबाद, तह० नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती पवन कुमारी पत्नि स्व० सुरेशचंद नाहटा,
3. अरविन्द नाहटा पुत्र स्व० सुरेशचंद नाहटा,
4. श्रीमती नीलम पुत्री स्व० सुरेशचंद नाहटा,
5. अक्षय नाहटा पुत्र स्व० सुरेशचंद नाहटा,
6. श्रीमती रानू पुत्री स्व० सुरेशचंद नाहटा, समस्त नि० केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
8. उप पंजीयक, केकड़ी ।
9. रामदेव पुत्र छीतर, जाति तेली, नि० केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 8.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 256/2014.

उपस्थित:—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांतस ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पोंड संख्या 1.
3. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पोंड संख्या 2 से 6.
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील रेस्पोंड संख्या 9.
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोंड संख्या 7 व 8.

निर्णय

दिनांक:—16.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.5.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांत ने अधी०न्याया० में वाद अंतर्गत धारा 53ख 92-ए, 188 एवं 209 राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की वाद वर्णित आराजियात वाके कस्बा केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 2428 में दर्ज आराजियात खसरा नंबर 1165, 1168 व 1169 कुल रकबा 2.78 है० भूमि दर्ज है । वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की व कब्जे काश्त की भूमियां है जिसमें वादी का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5, 6 व 7 का 1/2 हिस्सा है । विवादित

आराजियात का विधिक बंटवारा नहीं हुआ है व संयुक्त रूप से ही दर्ज है। प्रतिवादीगण आराजियात के विशेष भू-भाग का बैचान, अंतरण करना चाहते हैं। अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का विधिवत् रूप से बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाता दर्ज कर मालगुजारी कायम की जावे। विद्वान अधी०न्याया० ने दिनांक 8.5.2018 को वादी/अपीलांत का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की। अधी०न्याया० के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को तलब किया गया। रेस्पों के उपस्थित होने तथा अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांत ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व वादी/अपीलांत द्वारा प्रस्तुत वाद एवं जवाब के आधार पर तनकियात कायम किये बिना तथा बिना साक्ष्य लिये जवाब के आधार पर कोई फाईण्डिंग दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। वादग्रस्त आराजियात कुल रकबा 2.78 है० वादी एवं प्रतिवादीगण की अविभाजित संयुक्त रूप से काबिज काश्त सहखातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जिसमें वादी/अपीलांत का 2/6 हिस्सा, प्रतिवादी/रेस्पों संख्या 1 का 1/6 हिस्सा शेष रेस्पों संख्या 2 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा है। अधी०न्याया० के समक्ष मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत था। वाद के विचाराधीन रहते न्यायालय की बिना अनुमति के आराजी का विधि विरुद्ध हस्तांतरण किया गया जो सम्पत्ति अंतरण अधि० 19३८ एवं राज०काश्त०अधि० 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। प्रतिवादीगण को बिना विधिक विभाजन के आराजी विक्रय करने का अधिकार नहीं था तथा क्रेता भी वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं थे। इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांत ने 2008 आर०एल०डब्ल्यू० (2) पेज 1135 सुप्रीमकोर्ट का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। विद्वान वकील अपीलांत ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० ने वादी/अपीलांत को बिना तारीख पेश दिये पत्रावली तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी जेरकार होकर पत्रावली तलबी दस्ती दिनांक 9.5.2018 को लिखित प्रार्थना पत्र सहित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत की गई इसके बावजूद अधी०न्याया० ने प्रतिवादी/रेस्पों संख्या 9 का उसी दिन जवाब लेकर समस्त प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब मं अंकित संलग्न नजरी नक्शा के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम बिना तथा बिना साक्ष्य लिये व वादी/अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिये अपीलांत की उपस्थिति दर्ज कर उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। यह भी कथन किया कि अधी०न्याया० तनकीवार विवेचना किये बिना निर्णय पारित किया है। यह भी कथन किया कि वाद के विचाराधीन रहते वादी/अपीलांत ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा०दी० प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि उक्त उनवानी वाद में लिप्त आराजी पुश्तैनी होने बाबत एक प्रकरण माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद मं वर्णित आराजी खसरा नंबर 1165, 1168 व 1169 बाबत प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में मान० न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को हस्तांतरण, बैचान, तृतीय पक्ष के पक्ष को हस्तांतरण नहीं करने बाबत निर्णय पारित किया है इसके बावजूद अधी०न्याया० ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.5.2018 को निरस्त किया जावे

तथा प्रकरण अधी०न्याया० को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे वादी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत् रूप से निर्णित करे ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पोंडेंटस ने कथन किया कि विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात थी । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व उनके अन्य परिवारजन के मध्य आराजियात बात् पूर्व में विवाद हो गया था । वादी के पिता के काका रामदयाल ने वाद पत्र में वर्णित आराजियात में से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 व 7 के पिता सुरेशचंद नाहटा को विक्रय कर उनके 1/2 हिस्से का कब्जा संभला दिया था तब से रेस्पोंडेंट विवादित आराजियात पर हिस्से अनुसार काबिज है । वाद वर्णित आराजियात बाबत् पूर्व में वादी के पिता व उनके परिवारजन के मध्य जगदीश बनाम राज०सरकार के नाम से एक वाद अधी०न्याया० में विचाराधीन रहा जिसमें पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया था । रेस्पोंडेंट क्रयशुदा आराजी पर काबिज काश्त होकर तारबंदी करवा रखी है । पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है जिसका नजरी नक्शा अधी०न्याया० के समक्ष जवाब के साथ पेश किया था । अधी०न्याया० ने पूर्व बंटवारे के अनुसार वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।
6. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का निस्तारण करना उचित समझते हैं । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
7. प्रकरण में गुणवगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि अधी०न्याया० ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा उच्च न्यायालय की रोक होने के बावजूद प्रतिवादीगण के जवाबदावे के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । इस संबंध में अधी०न्याया० के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया गया । अधी०न्याया० ने वाद को निर्णित करने से पूर्व वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम नहीं की है जबकि अधी०न्याया० के समक्ष वादपत्र 53 राज०काश्त०अधि० के तहत भी पेश किया गया था । अधी०न्याया० को बंटवारे की डिक्री पारित करने से पूर्व वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए डिक्री पारित करनी चाहिये थी किन्तु अधी०न्याया० द्वारा ऐसा नहीं किया जो विधिक प्रक्रिया का स्पष्टतः उल्लंघन है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् मान० राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन है जिसमें अधी०न्याया० की पत्रावली तलब की गई थी इसके बावजूद अधी०न्याया० ने वाद को डिक्री किया है जिससे भी अधी०न्याया० के निर्णय को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् मान० अपर जिला सत्र न्यायाधीश, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 26. 5.2015 के द्वारा उभयपक्षों को विवादित आराजी का हस्तांतरण, बैचान, तृतीय पक्ष को हस्तांतरण नहीं करने बाबत् निर्णय पारित किया गया था जिसे भी अधी०न्याया० ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिससे भी अधी०न्याया० के निर्णय को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप

से स्वीकार योग्य तथा अधीन न्याया का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य प्रकरण अधीन न्याया को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.5.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीन न्याया को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मान 0 राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी एवं मान 0 अपर जिला सत्र न्यायाधीश, अजमेर के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 16.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर